(ग) ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई कार्यदल गठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने अभी तक संबद्ध उच्च न्यायालय को राष्ट्रीय साईकिल इण्डिया लिमिटेड, एल्गिन मिल्स कं० लिमिटेड, ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर टैक्सटाईल लिमिटेड और टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड को बन्द करने की अनुशंसा की है। मामला सम्बन्धित उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा हुआ है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए एक सुरक्षा तंत्र के रूप में राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा किसी कार्यदल का गठन नहीं किया गया।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु सुविधाएं बढ़ाने की मांग

6440. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र जैसी सुविधाएं दिए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या किसी सरकारी उपक्रम ने अपने उत्पादन क्षेत्र में विदेशी और निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इस पर सरकार की नीति क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) सरकार को कोई विशिष्ट अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, यदि कोई पृथक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो गुणावगुण के आधार पर उस पर विचार किया जाएगा।

HEC, Ranchi

6441. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, has not been prequalified to bid for the 3rd Sinter Plant Project of Bhilai Steel Plant, even though the Project Report was prepared on the basis of the design and technology for identical plant built by H.E.C. for Visakhapatnam Steel Plant and that the last Sinter Machine of Bhilai Steel Plant was supplied/erected by H.E.C. on turn-key basis ahead of schedule;

(b) whether the use of one unit (Dip-Rail Circular Cooler) patented by a German Company has been made obligatory, thereby making this company and its licences the main bidders;

(c) whether the estimated price at the time of moving the proposal was much less than the present estimate; and

(d) if so, what action Government are taking in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Orders placed through Wagon India Ltd.

6442. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRIMATI CHANDRAKALA PANDEY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of wagons (FWU) and the percentage thereof of the total wagons (FMU) that have been ordered for the year 1995-96 by Railway through Wagon India Ltd. (WIL);

(b) whether the above allotment through WIL is as per the prevailing practice followed so far;

(c) if not, the impact of the same on the wagon manufacturing industries under the purview of Wagon India Ltd. and the action taken by Government to ensure optimal utilisation of the capacities of the Wagon industry?